Media/LKo/0028

लखनऊ, 12 दिसंबर 2014 दैनिक जागरण | 9

संकट कायम रहने के आसार

राब्यू, लखनऊ : गन्ना मूल्य का तत्काल भुगतान कराने को सरकार द्वारा करीब 40 रुपये क्विंटल रियायत से किसानों का भला नहीं हो रहा। मिलों को लगभग 585 लाख क्विंटल से ज्यादा गन्ना बेचने के बाद भी किसान खाली हाथ है। गत पेराई सत्र का 1103 करोड़ रुपये से अधिक का भुगतान करने को मिलों ने हाथ खड़े कर दिए हैं।

गन्ना संकट इस भी बार कायम रहने की आशंका अधिक है क्योंकि चीनी की मंदी के चलते गत वर्ष की तुलना में तीन मिलें कम चल रही हैं। नवाबगंज, बिजनौर एवं टोडरपुर की मिलें पेराई शुरू करने से मना कर चुकी है। किसान राजपाल फंदपुरी का कहना है कि उक्त चीनी मिलों के क्षेत्र की गन्ने की फसल बर्बाद हो जाएगी। सरकार इस ओर ध्यान नहीं दे रही है। जिला गन्ना अधिकारी मिल मालिकों के हित साधने में लगे है। बिजनौर, मेरठ, बागपत एवं हापुड़ के गन्ना अधिकारियों पर मनमाने तरीके से पर्चियां वितरित कराने व घटतौली न रोकने की शिकायत शासन में करने वाले किसान नेता राकेश त्यागी का

गन्ना भुगतान

- वर्तमान सत्र में भी किसान खाली हाथ, तीन मिलों का पेराई से इन्कार

कहना है कि बकाया भुगतान कराने में जानबूझ कर ढील बरती जा रही है। मवाना, सिंभावली और मोदी समूहों की मिलों पर सर्वाधिक देनदारी है।

चीनी परता बढ़ा, गन्ना खरीद सुस्त : इस वर्ष मिलें कम चलने के बाद भी चीनी का उत्पादन बढ़ने के आसार हैं। गत सत्र की तुलना में इस बार चीनी रिकवरी में वृद्धि हो रही है। खासतौर से पश्चिम क्षेत्र की मिलों में रिकवरी .5 फीसद तक बढ़ी है। पूर्वांचल की मिलों में अपेक्षित रिकवरी अभी नहीं मिल पा रही। बाजार में चीनी के दाम स्थिर रहने से मिल मालिकों को भुगतान लटकाने का अवसर भी मिल रहा है। उधर कर्नाटक और महाराष्ट्र जैसे राज्यों द्वारा सस्ती चीनी बेचने से भी उप्र की मिलों की सिरदर्दी बढ़ी है।

बकाया भुगतान करोड़ रुपये में

वर्ष	बकाया रकम
2012-13	12.28
2013-14	1103.22
2014-15	121.59

नोट-दस दिसंबर तक प्राप्त विभागीय आंकड़ा।

इंडियन शुगर मिल्स एसोसिएशन की ओर से केंद्र को लिखे पत्र में मिलों का दर्द बयां किया गया है। कर्नाटक, महाराष्ट्र की मिलों द्वारा 24- 26 रुपये की दर से चीनी बेचना उप्र की मिलों को भारी पड़ रहा है।

क्रयकर छूट में अधिसूचना का इंतजार : सरकार द्वारा क्रय कर में छूट करने के एलान का लाभ चीनी मिलों को नहीं मिल पा रहा। मिलें चलाने के समझौते पर सरकार द्वारा अमल नहीं होने से मालिकों को भुगतान में विलंब का बहाना मिल रहा है। मालिकों का कहना है कि ऐसे हालात में भुगतान संकट गहरा सकता है। उधर किसान मोर्चा अध्यक्ष विजयपाल तोमर ने भुगतान में देरी के लिए सरकार व मिलों में मिलीभगत का आरोप लगाया है।